भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-506
उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल साक्षरता का एकीकरण

506 **श्रीमती रंजीत रंजनः**
श्री दिग्विजय सिंहः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कुल सरकारी विद्यालयों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या सहित कार्यशील कंप्यूटर प्रयोगशाला तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले सरकारी विद्यालयों की संख्या कितनी है;
(ख) वे सरकारी विद्यालय कौन-कौन से हैं जिनके पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अथवा डिजिटल साक्षरता शामिल है;
(ग) क्या विद्यालय स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा के लिए कोई राष्ट्रीय दिशा-निर्देश अथवा शैक्षणिक मानक उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) एआई-संबंधित शिक्षण हेतु प्रशिक्षित सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या कितनी है और क्या इस प्रशिक्षण में विषय-विशिष्ट क्षमता निर्माण शामिल है, तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इन कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु अधिगम परिणाम के आकलन किए गए हैं; और
(च) अवसंरचना तथा शिक्षक प्रशिक्षण में असमानताओं के कारण डिजिटल विभाजन के विस्तार को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क): यूडाइस+ 2024-25 के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसार कार्यशील आईसीटी प्रयोगशालाओं और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले विद्यालयों का विवरण, साथ ही सरकारी विद्यालयों की कुल संख्या, **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ख) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में एआई के महत्व और स्कूली पाठ्यक्रम में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है। नीति के पैरा 4.24 में उल्लेख है कि सभी स्तरों पर छात्रों में इन विभिन्न महत्वपूर्ण कौशलों को विकसित करने के लिए उपयुक्त चरणों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (जीसीईडी) आदि जैसे समकालीन विषयों की शुरूआत सहित सम्मिलित पाठ्यचर्या और शैक्षणिक पहल की जाएंगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने कक्षा 11 और 12 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें विकसित करने हेतु एक पाठ्यपुस्तक विकास दल का गठन किया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यपुस्तक में एनीमेशन और खेलों पर

एक परियोजना भी शामिल की है। कंप्यूटर विज्ञान कक्षा XI (अध्याय 3, https://ncert.nic.in/textbook.php?kecs1=ps-11) और सूचना विज्ञान अभ्यास कक्षा XI (अध्याय 2, https://ncert.nic.in/textbook.php?keip1=ps-8) की मौजूदा एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में एआई, आईओटी और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में उल्लेख किया गया है।

भारत सरकार ने एसओएआर (एआई तैयारी के लिए कौशल) शुरू किया है, जो एनईपी 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप एक राष्ट्रीय पहल, एआई संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएआई) स्किलिंग फ्रेमवर्क और डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशी विकास के विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के अनुरूप है। एसओएआर का उद्देश्य स्कूली छात्रों (कक्षा 6-12) के बीच एआई जागरूकता और मूलभूत दक्षताओं को शामिल करना और शिक्षकों के बीच एआई साक्षरता का निर्माण करना है। इस कार्यक्रम के तहत भौगोलिक क्षेत्रों में एआई शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करके डिजिटल अंतराल कम करने का प्रयास किया गया है, जिससे समावेशी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहायता की जा सके। एसओएआर पाठ्यक्रम में चार प्रगतिशील राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)-अनुकूलित मॉड्यूल शामिल हैं। कक्षा 6 से 12 के छात्रों के लिए, तीन अलग-अलग माइक्रो-क्रेडेंशियल्स: (i) जागरूक होने के लिए एआई, (ii) एआई का अधिग्रहण करना है, और (iii) एआई से एस्पायर, 15 घंटे की अवधि में से प्रत्येक को प्रस्तुत किया जाता है, जो कुल मिलाकर 45 घंटे की होती है। ये मौलिक एआई अवधारणाओं, व्यावहारिक प्रोग्रामिंग, नैतिक और जिम्मेदार एआई उपयोग और प्रौद्योगिकी में करियर के अवसरों को कवर करते हैं। शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के लिए एआई शीर्षक वाला एक 45 घंटे का मॉड्यूल एआई अवधारणाओं, शैक्षणिक रणनीतियों और व्यावहारिक कक्षा अनुप्रयोग में व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करता है।

इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल' (निष्ठा) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली शिक्षा स्तर पर सीखने के परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय मिशन लागू कर रहा है। निष्ठा के माध्यम से राष्ट्रीय संसाधन समूहों को शिक्षा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित किया जाता है और डिजिटल शिक्षकों को प्रमाणित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार करने के लिए निम्नलिखित कई पहलें की हैं: -

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 का कार्यान्वयन जिसमें स्कूल स्तर से कोडिंग, एआई, डेटा साइंस, डिजाइन थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग और अनुभवात्मक अधिगम पर एक मजबूत ध्यान देने के साथ बहु-विषयक, प्रौद्योगिकी-एकीकृत शिक्षा पर जोर दिया गया है।
- उद्योग और तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से ऑनलाइन एआई श्रृंखला, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पहल के माध्यम से शिक्षकों और छात्रों के लिए राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण कार्यक्रम।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षकों को उभरती प्रौद्योगिकियों के बारे में सूचित किया जाए, मंत्रालय और एनसीईआरटी हितधारकों के साथ नियमित रूप से क्षमता निर्माण/परामर्श कार्यशालाओं का आयोजन कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य अभिनव, शिक्षा-विशिष्ट एआई समाधानों की पहचान करना और जिम्मेदार एआई परिनियोजन में सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना है। दीक्षा टीम कक्षा निर्देश, मूल्यांकन और व्यक्तिगत शिक्षण में शिक्षकों की सहायता करने के लिए एआई-आधारित नई सुविधाओं और उपकरणों को शामिल करने पर भी लगातार काम कर रही है।
- शिक्षक संवेदीकरण/अभिमुखीकरण सत्र शिक्षकों और शैक्षणिक टीमों को एआई क्षमताओं, सीमाओं, नैतिक विचारों और सुरक्षित-उपयोग दिशानिर्देशों को समझने में मदद करते हैं, जिससे वे एआई उपकरणों को जिम्मेदारी से अपनी शैक्षणिक प्रथाओं में एकीकृत करने में सक्षम होते हैं।

(ङ): भारत सरकार देश में सीखने और शैक्षिक परिणामों के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर बड़े पैमाने पर आकलन करती है। इस संदर्भ में, विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के तत्वावधान में एनसीईआरटी के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र–परख द्वारा 'परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024' आयोजित किया गया।

छात्रों की शैक्षिक पृष्ठभूमि की व्यापक समझ प्राप्त करने और आकलन निष्कर्षों की अधिक समग्र व्याख्या सक्षम करने के लिए, सर्वेक्षण अभ्यास के हिस्से के रूप में विभिन्न संदर्भगत सामाग्री की जानकारी भी एकत्र की गई। ऐसे संदर्भगत चर में घर और विद्यालय में डिजिटल उपकरणों तथा इंटरनेट तक पहुँच शामिल थी।

परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर की रिपोर्टें उपलब्ध हैं, जो चरण-विशिष्ट दक्षताओं की उपलब्धि और प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले संदर्भगत चर पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये रिपोर्टें https://dashboard.parakh.ncert.gov.in/en पर उपलब्ध हैं, जो मूल्यांकन के निष्कर्षों के प्रसार के लिए तैयार किया गया एक समर्पित डैशबोर्ड है।

(च): सभी छात्रों द्वारा ऑनलाइन सीखने की सुविधा के लिए, 17 मई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के हिस्से के रूप में 'पीएम ईविद्या' नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई थी, जो देश भर में शिक्षा के लिए मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों की प्रभावकारिता का उपयोग, निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। पीएम ई-विद्या में राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों (एबी)/अन्य मंत्रालयों को आवंटित 200 डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल शामिल हैं ताकि वे कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में अपनी आवश्यकता के अनुसार पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें।

ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए साथ ही सभी कक्षा (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडेड एनर्जेइज्ड पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ देश का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों ने मातृभाषा/स्थानीय/क्षेत्रीय भाषाओं में 3.7 लाख से अधिक सामग्री तैयार की और योगदान दिया है, जिससे बहुभाषिकता को सक्षम बनाया गया है। सीमित या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए दीक्षा ऑफ़लाइन सुविधा उपलब्ध कराता है। हितधारकों को दीक्षा पर 450+ वर्चुअल लैब्स और 100 वर्चुअल स्किल लैब्स तक पहुँच प्राप्त है।

प्रबंध पोर्टल के अनुसार, अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को 1,79,153 आईसीटी प्रयोगशालाएँ और 1,76,738 स्मार्ट कक्षाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बजट 2025 में दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 'भारतनेट' परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की है।

******

अनुलग्नक

दिनांक 04 फरवरी, 2026 को "शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल साक्षरता के एकीकरण" से संबंधित माननीय संसद सदस्य श्रीमती रंजीत रंजन, श्री दिग्विजय सिंह और श्रीमती फूलो देवी नेताम द्वारा पूछा गया राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 506 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

कार्यशील आईसीटी लैब्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले विद्यालयों सहित सरकारी विद्यालयों की कुल संख्या की जानकारी का राज्यवार/संघ राज्य वार ब्यौरा निम्नलिखित है: -

क्र.सं.	राज्य/यूटी	कक्षा VI और उससे ऊपर के कुल सरकारी विद्यालयों की संख्या	इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले स्कूल	कार्यात्मक आईसीटी प्रयोगशालाओं वाले स्कूल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	160	148	136
2	आंध्र प्रदेश	10646	10583	1309
3	अरुणाचल प्रदेश	1269	436	140
4	असम	11282	10894	3946
5	बिहार	38355	32923	4871
6	चंडीगढ़	115	115	103
7	छत्तीसगढ़	18091	11852	932
8	डीएचएनडी-डीएनएच	211	210	160
9	दिल्ली	1157	1157	715
10	गोवा	132	130	47
11	गुजरात	22353	21759	12756
12	हरियाणा	5683	4683	2362
13	हिमाचल प्रदेश	4782	3663	1941
14	जम्मू एंड कश्मीर	9822	4329	2114
15	झारखंड	14527	8686	3515
16	कर्नाटक	28753	11631	2517
17	केरल	2426	2250	1378
18	लद्दाख	499	248	135
19	लक्षद्वीप	21	21	8
20	मध्य प्रदेश	34152	12933	2610
21	महाराष्ट्र	22538	14433	1037
22	मणिपुर	984	385	320
23	मेघालय	2352	769	113
24	मिज़ोरम	1342	904	270
25	नागालैंड	925	489	109
26	ओड़ीशा	21734	18654	4628
27	पुडुचेरी	186	186	116
28	पंजाब	6425	6353	84
29	राजस्थान	38019	27601	9870
30	सिक्किम	394	237	233
31	तमिलनाडु	13346	12678	11017
32	तेलंगाना	10309	6405	2529
33	त्रिपुरा	2135	1193	908
34	उत्तर प्रदेश	49418	18487	1794
35	उत्तराखंड	4902	3260	610
36	पश्चिम बंगाल	15479	9727	8480
	कुल	**3,94,924**	**2,60,412**	**83,813**

स्रोत: यूडाइज़+ 2024-25